Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

22nd AUGUST 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

22nd August 2022

1. - कानून के शासन के बारे में: 3
   (i) अर्थ: 3
   (ii) भारत और संविधान में कानून का शासन: 3

2. - बादल फटने की घटनाओं का विवरण: 4
   (i) के बारे में: 4
   (ii) घटना: 4
   (iii) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: 4
   (iv) भविष्यवाणी: 5

3. - पोलियो वायरस के बारे में: 6
   (i) के बारे में: 6
   (ii) तीन अलग-अलग जंगली पोलियोवायरस उपभेद हैं, प्रत्येक प्रतिरक्षा विज्ञान के मामले में दूसरों से अलग हैं: 6
   (iii) फैलाव: 6
   (iv) लक्षण: 6
   (v) रोकथाम और उपचार: 6
   (vi) टीके: 6
   (vii) हाल ही में हुए प्रकोप: 7
   (viii) भारत में पोलियो वायरस: 7

4. – आधार वोटर आईडी लिंकेज का विवरण: 8
(i) चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के कौन से प्रमुख घटक आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देते हैं? . 8
(ii) आधार को मतदाता पहचान पत्र सूची से जोड़ने के लिए इसे क्यों चुना गया? 8
(iii) मतदाता सूची और आधार को एक साथ इस्तेमाल करने पर क्या लाभ मिलते हैं? 9
(iv) आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से क्या समस्याएं आती हैं? 9
(v) क्या किये जाने की आवश्यकता है? 11

संपादकीय विश्लेषण 12

1. स्टेम सेक्टर में महिलाएं: 12
(i) के बारे में: 12
(ii) महत्व: 12
(iii) भारत में एसटीईएम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी: 12
(iv) कम भागीदारी के कारण: 12
(v) महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल: 13

2. चेहरे की पहचान तकनीक: 15
(i) चेहरे की पहचान क्या है? 15
(ii) चेहरे की पहचान के लाभ: 15
(iii) स्वचालित पहचान: 15
(iv) चेहरा पहचान तकनीक के विपक्ष: 17
(v) अभी भी योजना के चरणों में: 18

1. - कानून के शासन के बारे में:

GS II

विषय→संविधान संबंधित मुद्दे

अर्थ:

- शब्द "कानून का शासन", जो शुरू में इंग्लैंड में इस्तेमाल किया गया था, को भारत में स्वीकृति मिल गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून के शासन का उल्लेख है।
- कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उनकी स्थिति या स्थिति कुछ भी हो, और हर कोई सामान्य न्यायालयों के निर्णय के अधीन है, इसे सीधे शब्दों में कहें।
- कानून के शासन की अवधारणा में कहा गया है कि किसी के साथ मनमाना या कठोर व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- वाक्यांश "कानून का शासन" इस विचार को संदर्भित करता है कि कानून किसी व्यक्ति या शासक के बजाय व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों पर लागू होना चाहिए।
- "व्यापक आवेदन के कानूनी सिद्धांत, शासी निकायों या अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, और एक स्वयंसिद्ध के रूप में तैयार किया गया है" यह है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी "कानून के शासन" को कैसे परिभाषित करता है।
- ऐसी स्थिति जहां कानून राज्य और उसके प्रत्येक नागरिक को नियंत्रित करता है, उसे ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी में "कानून का नियम" कहा जाता है।

भारत और संविधान में कानून का शासन:

- सरकार की सभी तीन शाखाएं संविधान के अधीन हैं क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को न केवल इसके प्रावधानों का पालन करना चाहिए बल्कि उन्हें लागू भी करना चाहिए।
- न्यायिक समीक्षा को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, और लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि कार्यपालिका या सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करती है या बेईमानी से कार्य करती है, तो सामान्य न्यायालयों में उन कार्यों को रद्द करने की क्षमता होती है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कानून के शासन का विचार, जो इस मामले में कानूनी प्रणाली की वैधता के मानक के अनुसार सभी प्रशासनिक कार्यों का न्याय करने की क्षमता को संदर्भित करता है, हमारी संवैधानिक प्रणाली का मौलिक और सबसे विशिष्ट पहलू है। मुख्य बंदोबस्त आयुक्त पंजाब बनाम ओम प्रकाश में।
- कोर्ट ने कहा कि दोहरे राज्य का विचार, जिसमें न्यायिक निरीक्षण से छूट की विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में सरकारी कार्रवाई को बनाए रखा जाता है, कानून की अवधारणा के शासन द्वारा खारिज कर दिया गया है।

- *स्रोत→ हिन्दू*

2. - बादल फटने की घटनाओं का विवरण:

GS I

विषय→भूगोल से संबंधित मुद्दे

के बारे में:

- बादल फटना संक्षिप्त, शक्तिशाली वर्षा है जो विशिष्ट स्थानों पर होती है।
- 20 से 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक की अप्रत्याशित वर्षा को इस मौसम संबंधी घटना के रूप में जाना जाता है।
- यह भारतीय उपमहाद्वीप में अक्सर होता है क्योंकि मानसून बादल अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से हिमालय तक जाता है, मैदानी इलाकों को पार करता है और कभी-कभी हर घंटे 75 मिलीमीटर तक बारिश करता है।

घटना:

- कम तापमान और कम हवाओं के कारण सापेक्ष आर्द्रता और बादल कवर अपने अधिकतम स्तर पर हैं, जिससे कई बादल जल्दी से संघनित हो सकते हैं और बादल फट सकते हैं।
- जब तापमान बढ़ता है, तो आकाश अधिक से अधिक नमी धारण कर सकता है, और यह नमी थोड़ी देर के लिए तेज, तीव्र बारिश के रूप में बारिश कर सकती है, आमतौर पर आधे या एक घंटे के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और शहरों में शहरी बाढ़ पैदा कर सकती है।
- बादल फटना अचानक, भारी बारिश होती है जो बारिश से अलग होती है क्योंकि बारिश बस बादल से गिरने वाला गाढ़ा पानी है।
- 100 मिमी प्रति घंटे से अधिक की वर्षा को बादल फटना कहा जाता है।
- बादल फटना स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन यह अचानक, बेहद अप्रत्याशित रूप से और बहुत अधिक बारिश के साथ होता है।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

- कई अध्ययनों से पता चला है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप बादल फटना अधिक सामान्य और तीव्र हो जाएगा।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, मई 2021 में इस संभावना को बताने वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, वार्षिक औसत वैश्विक तापमान में निम्न पांच वर्षों में से कम से कम एक में पूर्व-औद्योगिक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 90% संभावना मौजूद है कि 2021 और 2025 के बीच कम से कम एक वर्ष 2016 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में पार कर जाएगा।
- यह ध्यान दिया जाता है कि वहाँ अधिक बादल फटते हैं क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में दशकीय तापमान वृद्धि वैश्विक स्तर पर तापमान वृद्धि की दर से अधिक है।

भविष्यवाणी:

- चूंकि बादल फटने का विस्तार तेजी से होता है, इसलिए यह अनुमान लगाने का कोई सटीक तरीका नहीं है कि वे कब घटित होंगे।
- बादल फटने की संभावना को निर्धारित करने के लिए रडार के एक महंगे, बहुत सटीक नेटवर्क की आवश्यकता होती है।
- कम दूरी के आधार पर केवल उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जहां अधिक वर्षा होने की संभावना है। बादलों के फटने के विकास को प्रोत्साहित करने वाले स्थानों और मौसम संबंधी कारकों को समझकर बहुत से नुकसान से बचा जा सकता है।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

GURU DEEKSHAA IAS

3. - पोलियो वायरस के बारे में:

GS II

विषय→स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

के बारे में:

- पोलियो के रूप में जाना जाने वाला अपंग और संभावित घातक वायरल संक्रमण तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है।

तीन अलग-अलग जंगली पोलियोवायरस उपभेद हैं, प्रत्येक प्रतिरक्षा विज्ञान के मामले में दूसरों से अलग हैं:

- जंगली पोलियोवायरस टाइप 1 (WPV1)
- जंगली पोलियोवायरस टाइप 2 (WPV2)
- जंगली पोलियोवायरस टाइप 3 (WPV3)

- एक ही लक्षण, जैसे अपरिवर्तनीय पक्षाघात या यहां तक कि मृत्यु, तीनों उपभेदों में मौजूद हैं। आनुवंशिक और वायरोलॉजिकल मतभेदों के कारण, ये तीन उपभेद अद्वितीय वायरस हैं जिन्हें अलग-अलग मिटाया जाना चाहिए।

फैलाव:

- वायरस सबसे अधिक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मल और मुंह के माध्यम से फैलता है, जबकि यह एक साझा वाहन (उदाहरण के लिए, दूषित पानी या भोजन के माध्यम से) के माध्यम से भी कम बार हो सकता है।
- अधिकांश प्रभावित बच्चे पांच साल से कम उम्र के हैं। तंत्रिका तंत्र में जाने से पहले वायरस बृहदान्त्र में विकसित होता है, जहां यह पक्षाघात का कारण बन सकता है।

लक्षण:

- अधिकांश पोलियो रोगी अच्छे स्वास्थ्य में होने का दावा करते हैं। बुखार, थकावट, जी मिचलाना, सिर दर्द, हाथ-पैर में दर्द आदि जैसे मामूली लक्षण केवल कुछ रोगियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं।
- कुछ मामलों में, पोलियो संक्रमण मांसपेशियों के कार्य (पक्षाघात) के स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है।
- पोलियो घातक हो सकता है यदि मस्तिष्क संक्रमित हो जाता है या श्वास की मांसपेशियों को लकवा मार जाता है।

रोकथाम और उपचार:

- कोई इलाज न होने पर भी टीके इसे रोकने में मदद कर सकते हैं।

टीके:

- ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी): संस्थागत प्रसव के लिए, यह टीका मौखिक रूप से जन्म खुराक के रूप में दिया जाता है, छह, दस और चौदह सप्ताह में तीन प्राथमिक खुराक और सोलह से चौबीस महीने की उम्र में एक बूस्टर खुराक दी जाती है।

- DPT (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) की तीसरी खुराक के साथ, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के हिस्से के रूप में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन (IPV) दिया जाता है।

हाल ही में हुए प्रकोप:

- 2019 में, फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चीन, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में पोलियो का प्रकोप दर्ज किया गया था। इन प्रकोपों में से अधिकांश वैक्सीन-व्युत्पन्न थे, जिसका अर्थ है कि वायरस का एक दुर्लभ स्ट्रेन आनुवंशिक रूप से टीकाकरण में इस्तेमाल किए गए स्ट्रेन से अलग हो गया है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यदि मौखिक वैक्सीन वायरस को कम से कम 12 महीनों के लिए असुरक्षित या कम टीकाकरण वाली आबादी में प्रसारित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह बीमारियों (विश्व स्वास्थ्य संगठन) का कारण बन सकता है।

GURU DEEKSHAA IAS

भारत में पोलियो वायरस:

- तीन साल तक बिना किसी मामले के 2014 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।
- सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने वाले प्रभावी पल्स पोलियो अभियान ने इस उपलब्धि को संभव बनाया।
- 13 जनवरी, 2011 को देश में पोलियो का अंतिम मामला सामने आया था।

- *स्रोत→ हिन्दू*

4. – आधार वोटर आईडी लिंकेज का विवरण:

GS II

विषय→चुनाव संबंधित मुद्दे

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 के कौन से प्रमुख घटक आधार को मतदाता सूची से जोड़ने की अनुमति देते हैं?

- आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना: 1950 के अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को एक आवेदन जमा करके अनुरोध कर सकता है कि उनका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ा जाए। अधिकारी आदेश देगा कि आवेदक का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, यदि सत्यापन के बाद, यह निर्धारित किया जाता है कि आवेदन पंजीकरण के लिए योग्य है।
- बिल के अनुसार मतदाता पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए उनका आधार नंबर मांग सकता है। यदि उनका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, तो उनकी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए उनके आधार नंबर की आवश्यकता हो सकती है।
- चुनावी रिकॉर्ड से कोई नाम नहीं हटाया जाएगा क्योंकि कोई आधार नंबर नहीं दे सका, और उनके नाम जोड़ने के सभी अनुरोधों को मंजूरी दे दी जाएगी। कोई और वैकल्पिक कागजी कार्रवाई जिसकी आवश्यकता हो सकती है, इन लोगों से प्राप्त की जा सकती है।
- सरकार तय करेगी कि लिंक न करने के वैध औचित्य के रूप में क्या योग्य है: लोगों को अपने आधार को लिंक न करने का विकल्प देने के लिए, सरकार परिभाषित करेगी कि "पर्याप्त कारण" क्या है।

आधार को मतदाता पहचान पत्र सूची से जोड़ने के लिए इसे क्यों चुना गया?

- 2015 राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण और प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एनईआरपीएपी): डुप्लिकेट नामों को खत्म करने के प्रयास में, चुनाव आयोग के पास एक कार्यक्रम है जो मतदाता पहचान पत्र और आधार को जोड़ता है। यह प्रणाली आधार और चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) से मतदाता डेटा को भी जोड़ती है और प्रमाणित करती है।
- एनईआरपीएपी लागू होने से पहले, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2014 में निजामाबाद और हैदराबाद जिलों में दो पायलट कार्यक्रम आयोजित किए थे।
- बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग को आधार को मतदाता जानकारी से जोड़ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह "पूरी तरह से स्वैच्छिक" है और "इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि इस न्यायालय द्वारा किसी भी तरह से मामले का पूरी तरह से फैसला नहीं किया जाता।" उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को वैकल्पिक बना दिया।
- इस साल की शुरुआत में, चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक पत्र भेजकर अधूरे चुनाव सुधारों, विशेष रूप से आधार और मतदाता पहचान पत्र के बीच के लिंक पर "तेजी से विचार" करने के लिए कहा।

- संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश: अपनी 105 वीं रिपोर्ट में, कार्मिक, लोक शिकायत और कानून और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने मतदाता पंजीकरण सूचियों को शुद्ध करने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का सुझाव दिया और इसके परिणामस्वरूप, मतदाता सूची को कम किया। धोखा।

मतदाता सूची और आधार को एक साथ इस्तेमाल करने पर क्या लाभ मिलते हैं?

- प्रशासन का दावा है कि आधार को चुनावी रिकॉर्ड से जोड़ने से कई तरह की दिक्कतें दूर होंगी.
- पुनरावृत्ति से बचने के लिए: आवासीय पते लगातार बदले जा रहे हैं। इसलिए पूर्व के नामांकन को हटाए या रद्द किए बिना नए क्षेत्रों में वही नाम या नामांकन हुआ है।
- आधार से लिंक होने के बाद, मतदाता सूची डेटा सिस्टम स्वचालित रूप से एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में या एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार किसी व्यक्ति के पंजीकरण की पहचान करेगा।
- उस क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करें जहां वे "आमतौर पर निवास करते हैं।"
- आधार, ईपीआईसी के विपरीत, बायोमेट्रिक जानकारी को कैप्चर करता है जो विशिष्टता सुनिश्चित करने में सहायक है, इसलिए यह प्रॉक्सी मतदाताओं से छुटकारा पा सकता है जो कई मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करते हैं।
- निवास आदि में परिवर्तन के लिए सभी समायोजन आसानी से किए जा सकते हैं और सत्यापित किए जा सकते हैं, सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक मतदान प्रदान करते हैं।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिकांश वयस्कों के पास आधार संख्या है, और 31 अक्टूबर, 2021 तक 1,260 मिलियन से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके होंगे।
- इसलिए आधार को चुनावी रिकॉर्ड से जोड़कर पंजीकरण, सत्यापन, पते में परिवर्तन और त्रुटियों और चूक के सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- भविष्य में कहीं से भी (और उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी) मतदान उपलब्ध होगा, जिससे मतदाता अपने घरों या अन्य चुने हुए स्थानों से अपने मतपत्र डाल सकेंगे।

आधार को मतदाता सूची से जोड़ने से क्या समस्याएं आती हैं?

आधार डेटाबेस में समस्या आ रही है:

- आधार डेटाबेस कभी-कभी उंगलियों के निशान या यहां तक कि आईरिस स्कैन से मेल नहीं खाता है।
- आधार डेटा में डेटा उल्लंघनों और खराब डेटा गुणवत्ता के उदाहरण हैं।
- आधार डेटाबेस में रखी गई जनसांख्यिकीय जानकारी की सटीकता का कोई सत्यापन नहीं है। उदाहरण के लिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों ने आधार डेटा की वैधता को चुनौती दी है।
- आधार डेटा की प्रभावशीलता सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट का विषय नहीं है।

- राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार असफल आधार प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप बहिष्करण दर 49% से 5% तक है। इसलिए, इसे चुनाव रिकॉर्ड से जोड़ने से वोटर आईडी डेटाबेस में जानकारी की सटीकता खतरे में पड़ सकती है।
- यह अधिनियम निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी मामले में परिभाषित किया था।
- सबूत के दायित्व में बदलाव पहले, सरकार ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (उदाहरण के लिए, घर-घर सत्यापन के माध्यम से) प्राप्त करने के लिए मतदाता सूची पर मतदाता पंजीकरण को दृढ़ता से लागू किया था। यह अब उन लोगों पर निर्भर है जो रोल पर अपनी निरंतर उपस्थिति के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करने के लिए अनिच्छुक या अपने आधार को लिंक करने में असमर्थ हो सकते हैं।
- जैसा कि आधार अधिनियम में कहा गया है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जिससे गैर-नागरिकों को मतदान से रोकना असंभव हो जाता है। हालांकि, मतदान केवल नागरिकों तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में, मतदाता पहचान के लिए आधार की आवश्यकता गैर-नागरिकों को मतदान करने से नहीं रोकेगी।
- **जनसांख्यिकीय डेटा समस्याएं:**आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने का कोई भी प्रयास इस तरह के डेटा का उत्पादन करेगा। आलोचकों का दावा है कि मतदाता पहचान डेटा का उपयोग करते हुए, सरकार "विशेष नागरिकों को वंचित करने और आबादी को प्रोफाइल करने" में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, इसे राजनीतिक प्रचार के लिए एक लॉन्चपैड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे जानबूझकर लक्षित किया जाता है और निजी जानकारी के व्यावसायिक शोषण के लिए, दोनों ही आदर्श आचार संहिता के खिलाफ जाते हैं।
- उदाहरण के लिए, 2018 में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारियों ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार डेटा के साथ जोड़ दिया। कार्यकर्ताओं के अनुसार, लोगों ने पाया कि कम से कम 5.5 मिलियन मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार को दबा दिया था। बाद में सरकार ने अपना इरादा बदल दिया।
- इसे आवश्यक किए बिना, जोड़ने से काम नहीं चलेगा: आधार देना आवश्यक होने पर ही उपरोक्त सूचीबद्ध सरकारी भत्ते दिए जाएंगे।
- अगर सरकार आधार को लिंक नहीं करने के लिए "पर्याप्त आधार" को परिभाषित करने में विफल रहती है, तो मतदाताओं के वोट का अधिकार छीना जा सकता है। यदि वे जानकारी प्रस्तुत करने से इनकार करते हैं तो उनके मताधिकार को खोने का खतरा होता है और इसे "अनुचित" माना जाता है।
- **एक ऐसी स्थिति जिसमें सरकारी अधिकारी का निर्णय उसकी व्यक्तिगत रूचि से प्रभावित हो:**मतदाता सूची को अद्यतित रखना अनिवार्य रूप से एक स्वतंत्र संवैधानिक संगठन ECI की जिम्मेदारी है। आधार एक सरकारी उपकरण है, जबकि यूआईडीएआई सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह देखते हुए कि आधार नामांकन या डुप्लीकेशन पर चुनाव आयोग का कोई प्रभाव नहीं है, हितों का टकराव हो सकता है।
- अन्य मुद्दों में ईसीआई और यूआईडीएआई के डेटाबेस के बीच डेटा साझा करने की सीमा, सहमति प्राप्त करने के

तरीके, और सहमति रद्द की जा सकती है या नहीं, निर्दिष्ट करने में योजना की विफलता शामिल है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- हालांकि ऐसे दावे किए गए हैं कि गैर-नागरिकों को वोट देने के लिए पंजीकृत किया गया है और कुछ मतदाताओं के पास कई पंजीकरण हो सकते हैं, इन मुद्दों को विभिन्न पहचान विधियों को नियोजित करके हल किया जा सकता है।

- महज दो दिनों में दोनों सदनों ने विधेयक को मंजूरी दे दी। यह संसदीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करता है। इसलिए, प्रशासन को नए कानूनों को लागू करने से पहले जनता से प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए और अधिक व्यापक विधायी समीक्षा की अनुमति देनी चाहिए। एक संसदीय समिति को प्रासंगिक चिंताओं का विश्लेषण करना चाहिए और उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए।

GURU DEEKSHAA IAS

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

संपादकीय विश्लेषण

1. स्टेम सेक्टर में महिलाएं:

के बारे में:

- संगठन ने पहले उन विषयों या एक पाठ्यक्रम में रोजगार क्षेत्रों का उल्लेख किया था जिसमें उन क्षेत्रों से ज्ञान और कौशल शामिल थे जो कि संक्षिप्त नाम SMET का उपयोग करते थे।
- छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पढ़ाने के लिए एक पाठ्यक्रम सभी चार विषयों के लिए एक अंत:विषय दृष्टिकोण को लागू करने के आधार पर आधारित है।
- भारत उन देशों में से एक है जो सबसे अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का उत्पादन करता है, और पिछले कई वर्षों के दौरान, एसटीईएम ने महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे।

महत्व:

- अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तनकर्ता, समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक अच्छी एसटीईएम शिक्षा द्वारा निर्मित होते हैं।
- नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, अगले दस वर्षों में पैदा होने वाली 80% नई नौकरियों के लिए गणित और विज्ञान का ज्ञान आवश्यक होगा।

भारत में एसटीईएम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी:

- भारत में महिला एसटीईएम स्नातक (43%) का उच्चतम अनुपात है, लेकिन वहां महिला एसटीईएम कर्मचारियों का सिर्फ 14% है।
- भारतीय एसटीईएम क्षेत्रों में स्नातकों का प्रतिशत, जो अंततः एसटीईएम नौकरियों को प्राप्त करते हैं, ने हमेशा महिला स्नातकों के समग्र अनुपात की तुलना में अधिक प्रश्न उठाए हैं।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लचीली कार्य व्यवस्था और लिंग-तटस्थ वेतन प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। S&T व्यवसाय की दुनिया में आ गया है, और संस्थान इस तरह से बने हैं।
- जैसे-जैसे महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में अधिक भाग लेती हैं, समाज में उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, जिससे वे मजबूत और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगी।

कम भागीदारी के कारण:

- रूढ़िबद्धता: कौशल अपर्याप्तता के अलावा, निर्दिष्ट रूढ़िबद्ध लिंग भूमिकाओं ने एसटीईएम व्यवसायों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में योगदान दिया है।

- पितृसत्ता: पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को भर्ती प्रथाओं, छात्रवृत्ति और फैलोशिप कैसे दी जाती है, और अन्य क्षेत्रों में देखा जा सकता है।
- समाज: घरेलूता की सीमाएं, सकारात्मक रोल मॉडल की कमी, और फिट होने के लिए सामाजिक दबाव।
- विवाहित, बच्चे पैदा करना, और अन्य तनाव।
- घर के प्रबंधन का एक हिस्सा बुजुर्गों की देखभाल कर रहा है।
- काम पर जाते समय अपनी शारीरिक सुरक्षा को बनाए रखना।
- कार्यस्थल में, उत्पीड़न कई अलग-अलग रूप ले सकता है, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल:

विज्ञान ज्योति योजना:

- इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा पेश किया गया था।
- कॉलेज में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाली हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, यह खेल के मैदान को समतल करना चाहता है।
- इसके अतिरिक्त, यह दूर-दराज के क्षेत्रों की छात्राओं को स्कूल से विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाने में मदद करने के लिए एक्सपोजर देता है।

गति योजना:

- ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए जेंडर एडवांसमेंट एक व्यापक चार्टर और एसटीईएम (जीएटीआई) में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक प्रणाली प्रदान करेगा।
- पोषण के माध्यम से ज्ञान अनुसंधान उन्नति (किरण):
- 2014-15 में लागू की गई पहल की बदौलत महिला वैज्ञानिकों के पास अकादमिक और प्रशासन में अपने करियर को बढ़ाने का अवसर है।
- किरण कार्यक्रमों में से एक, "महिला वैज्ञानिक योजना", बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को देती है, विशेष रूप से वे जिन्होंने पेशेवर विश्राम, करियर विकल्प लिया है।

आगामी कदम उठाने होंगे:

- समस्या से दो स्तरों पर निपटा जाना चाहिए: सामाजिक स्तर, जिसके लिए चल रहे काम की आवश्यकता होती है, और संस्थागत और नीति स्तर, जहां तत्काल कार्रवाई संभव है।
- एसटीईएम प्रमुखों में चल रहे लिंग अंतर को हल करने के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को प्रोत्साहित करने, निर्णय लेने की पारदर्शिता बढ़ाने आदि में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।

- लेकिन लड़कियों को कॉलेज में एसटीईएम विषयों में विशेषज्ञता और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले, स्कूलों को पहले "प्रतिभा के लिंग आदर्शों" को समाप्त करना होगा।
- यह महिलाओं को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के अलावा विभिन्न दृष्टिकोणों की अनुमति देकर अनुसंधान को बढ़ाएगा।
- यह स्पष्ट है कि चीजें बेहतर हो रही हैं क्योंकि एसटीईएम क्षेत्रों में अधिक महिलाएं हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। अभी भी काफी लम्बा रास्ता पड़ा है।

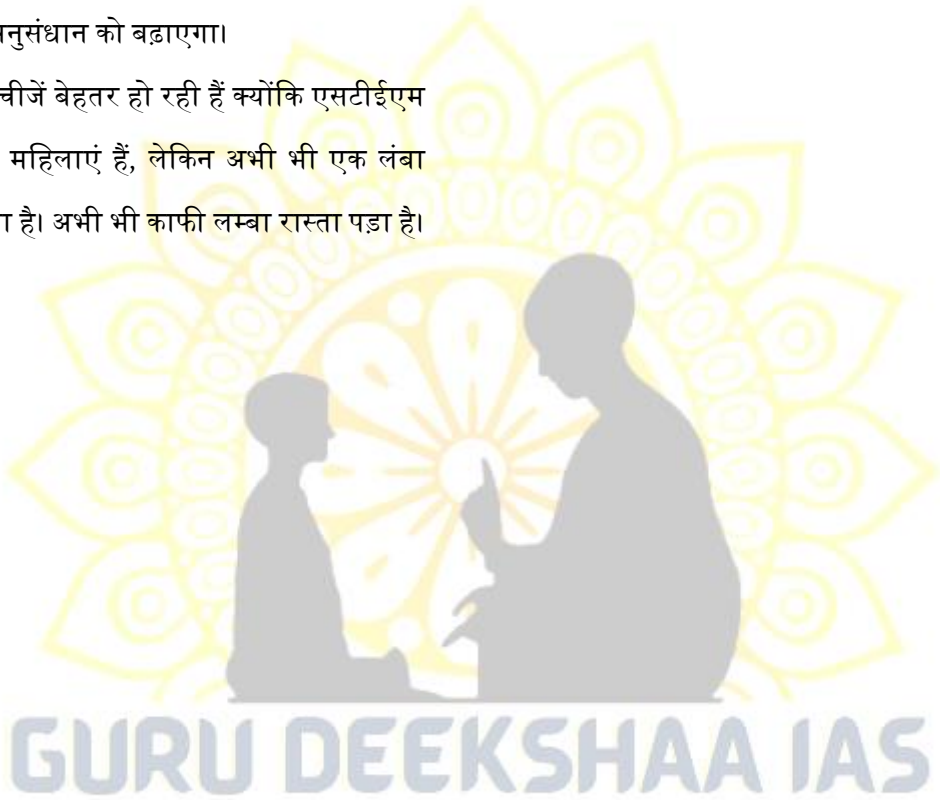

2. चेहरे की पहचान तकनीक:

चेहरे की पहचान क्या है?

- चेहरे की पहचान एक प्रकार की बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट चेहरे के लक्षणों को पहचानने और उन्हें अलग करने के लिए उपयोग करती है।

- AFRS द्वारा चलने के लिए फ़ोटो और चेहरों के वीडियो का एक विशाल डेटाबेस बनाए रखा जाता है। फिर, एक अज्ञात व्यक्ति की एक ताजा छवि की तुलना वर्तमान डेटाबेस से की जाती है ताकि एक मैच ढूंढा जा सके और व्यक्ति की पहचान की जा सके। इस दृश्य को कैद करने के लिए आमतौर पर सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल किया जाता है।
- पैटर्न का पता लगाने और मिलान के लिए उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक को "तंत्रिका नेटवर्क" के रूप में जाना जाता है।

चेहरे की पहचान के लाभ:

बढ़ाई गई सुरक्षा :

- चेहरे की पहचान की प्रभावशीलता को 3डी बायोमेट्रिक सिस्टम और इन्फ्रारेड कैमरों के उपयोग से बढ़ाया जा सकता है।
- कर्मचारियों और मेहमानों पर नज़र रखने से व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।
- चेहरे की पहचान की सहायता से किसी भी अतिचार, लुटेरों या अन्य घुसपैठियों को ढूंढना आसान होगा।
- सरकारी एजेंसियां चेहरे की पहचान का उपयोग आतंकवादियों या अन्य अपराधियों की पहचान करने के लिए उनके चेहरे को स्कैन करके कर सकती हैं। अतिरिक्त लाभ यह है कि प्रौद्योगिकी से समझौता नहीं किया जा सकता क्योंकि पासवर्ड के विपरीत, लेने या बदलने के लिए कुछ भी नहीं है।
- जब निजी उपयोग की बात आती है तो निजी उपकरणों को लॉक करने और निजी सुरक्षा कैमरों के लिए चेहरा पहचान एक सुरक्षा तकनीक हो सकती है।

त्वरित प्रसंस्करण:

- एक चेहरे को लगभग एक सेकंड में पहचाना जा सकता है, जो व्यवसायों के लिए काफी मददगार है।
- नियमित साइबर हमले और परिष्कृत हैकिंग टूल के युग में, व्यवसाय ऐसी तकनीक की तलाश करते हैं जो तेज और सुरक्षित हो। चूंकि चेहरे की पहचान लगभग तात्कालिक है, यह किसी व्यक्ति के त्वरित और कुशल सत्यापन को सक्षम बनाता है। इस तकनीक को बरगलाने की कठिनाई एक और फायदा है।

स्वचालित पहचान:

- अतीत में, सुरक्षा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की पहचान करनी पड़ती थी, जो गलत था और इसमें बहुत अधिक समय लगता था। हालांकि, आधुनिक चेहरे की पहचान तकनीक पिछली पहचान तकनीकों से पूरी तरह से स्वतंत्र है, त्वरित और बेहद सटीक है।

- 3डी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के विकास और इन्फ्रारेड कैमरों के उपयोग ने चेहरे की पहचान सटीकता के स्तर में काफी सुधार किया और इसे छल करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया।

नियमित एकीकरण:

- चेहरे की पहचान की तकनीक को एकीकृत करना अपेक्षाकृत आसान है। एकीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है क्योंकि अधिकांश चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकियां अधिकांश सुरक्षा कार्यक्रमों के अनुकूल हैं। एक वास्तविक जीत की स्थिति।

स्पर्श बिंदुओं की संख्या कम कर देता है:

- फ़िंगरप्रिंटिंग जैसी पारंपरिक सुरक्षा प्रक्रियाओं की तुलना में चेहरे की पहचान कम मानव संसाधनों का उपयोग करती है। इसके अलावा, इसमें व्यक्तियों के साथ आमने-सामने या शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रक्रिया को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के लिए AI का उपयोग करता है।
- दरवाजे खोलने, स्मार्टफोन अनलॉक करने, एटीएम का उपयोग करने, या कोई अन्य कार्य करने के लिए आवश्यक स्पर्श बिंदुओं की मात्रा भी कम हो जाती है जिसके लिए परंपरागत रूप से पिन, पासवर्ड या कुंजी की आवश्यकता होती है।

कम रोगाणु सामग्री:

- यात्रियों को हर दूसरे एयरपोर्ट चेकपॉइंट पर अपने हैंड सैनिटाइज़र के लिए पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां उन्हें पहचान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है क्योंकि चेहरे की पहचान के लिए शारीरिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है।

लापता को खोजने में मदद करता है:

- बच्चों सहित लापता लोगों को खोजने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग किया गया है।
- जब सॉफ्टवेयर के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है जो उम्र बढ़ने का अनुकरण करता है और भविष्यवाणी करता है कि भविष्य में बच्चा कैसा दिखेगा, तो चेहरे की पहचान तकनीक किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान करने में भी मदद कर सकती है जो लंबे समय से लापता है।

चिकित्सा उपचार को बढ़ाता है:

- चेहरे की पहचान तकनीक का एक अप्रत्याशित उपयोग आनुवंशिक विकारों का पता लगाना है।
- कुछ मामलों में, चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर यह निर्धारित करने में सक्षम हो सकता है कि चेहरे की सूक्ष्म विशेषताओं का विश्लेषण करके कौन सी विशिष्ट आनुवंशिक असामान्यताएं किसी विशेष बीमारी का कारण बनती हैं। पारंपरिक आनुवंशिक परीक्षण की तुलना में प्रक्रिया तेज और कम खर्चीली हो सकती है।

चेहरा पहचान तकनीक के विपक्ष:

- डेटा प्रतिधारण: आज दुनिया में मौजूद डेटा की मात्रा के साथ, डेटा संग्रहण अमूल्य है। चाहे वह बहुत अच्छी फिल्म हो या स्टोर करने के लिए 100,000 चेहरे, हर चीज में जगह की जरूरत होती है। तदनुसार, चेहरे की पहचान प्रणालियों के काम करने के लिए केवल 10 से 25 प्रतिशत फिल्म का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।
- इसका मुकाबला करने के लिए, कई व्यवसाय सूचनाओं को संभालने और प्रसंस्करण समय को कम करने के लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हालाँकि, यह बाधा तब तक दूर नहीं होगी, जब तक कि तकनीक महत्वपूर्ण प्रगति न कर ले।

भेद्यता को समझना:

- चेहरे की पहचान तकनीक की सटीकता पर विवाद नहीं किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, कैमरे की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन या आपके देखने का तरीका अनिवार्य रूप से एक त्रुटि का कारण बनेगा।
- किसी चेहरे को संसाधित किया जाए या नहीं, इसमें कैमरा कोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक चेहरे की पहचान प्रणाली को विभिन्न कोणों से चेहरे को पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें फ्रंटल, 45 डिग्री, प्रोफाइल और बहुत कुछ शामिल है, जो निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां पेश करेगा।

लोगों और समाज दोनों के निजता के अधिकार को खतरा है:

- पुलिस आधुनिक तकनीक की मदद से चोरों का पता लगा सकती है। हालाँकि, यह किसी को भी, कभी भी, कहीं भी ढूँढने की क्षमता रखता है।
- चेहरे की पहचान तकनीक द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए संभावित जोखिम एक गंभीर नकारात्मक है। लोग संभावित भविष्य के उपयोग के लिए डेटाबेस में अपने चेहरे की तस्वीरें एकत्र और संग्रहीत करने पर आपत्ति जताते हैं।
- कैंब्रिज, मैसाचुसेट्स और सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया सहित कुछ समुदायों ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण कानून प्रवर्तन द्वारा रीयल-टाइम फेस रिकग्निशन सर्विलांस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन परिस्थितियों में पुलिस द्वारा सुरक्षा कैमरा वीडियो के उपयोग की अनुमति है, लेकिन वास्तविक समय में चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग नहीं है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में नियमों का अभाव है:

- स्पर्श-मुक्त बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के उपयोग को विनियमित करने के लिए दुनिया की किसी भी सरकार के पास स्पष्ट नीति या दिशानिर्देशों का सेट नहीं है। दुनिया भर के कुछ शहरों और क्षेत्रों ने पहले ही इस तकनीक को अवैध बना दिया है क्योंकि इससे लोगों को संभावित नुकसान होता है। दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही

चेहरा पहचान-आधारित उपस्थिति प्रणाली कार्यरत हैं, हालांकि ये स्थान अनियमित हैं। नतीजतन, बड़ी संख्या में लोगों का डेटा पहले से ही खतरे में है।

कार्यान्वयन लागत अधिक है:

- तकनीक की एक कीमत होती है। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर बेहद जटिल है और सटीकता और गति सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कैमरों की आवश्यकता होती है।

अभी भी योजना के चरणों में:

- हालांकि अत्यधिक परिष्कृत, चेहरे की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर सही नहीं है। नस्लीय या लिंग भेद निर्धारित करने में एआई की सटीकता अभी भी बहस का विषय है। वजन में बदलाव, हेयर स्टाइल में बदलाव और यहां तक कि चेहरे के बालों के विकास सहित कई तकनीकों को उपस्थिति में बदलाव का ट्रैक रखने में भी परेशानी होती है।

किसी की पसंद की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है:

- चीन, संयुक्त अरब अमीरात, उत्तर कोरिया, ईरान और इराक जैसे सीमित नागरिक अधिकारों वाले देशों में, चेहरे की पहचान नियमित रूप से नागरिकों की जासूसी करने और संकटमोचक समझे जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए उपयोग की जाती है।

डेटा में कमियां पैदा होती हैं:

- चेहरे की पहचान डेटा भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस की सुरक्षा एक और चिंता का विषय है।
- बैंकों, पुलिस विभागों और रक्षा संगठनों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए फेशियल स्कैन डेटाबेस को हैकर्स द्वारा पहले ही भंग कर दिया गया है।

धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को होने में सक्षम बनाता है:

- यहां तक कि फेशियल रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल कर अपराधी निर्दोष पीड़ितों पर हमला कर सकते हैं। वे पहचान धोखाधड़ी करने के लिए लोगों के बारे में संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चेहरे के स्कैन के माध्यम से लिए गए फ़ोटो और वीडियो और डेटाबेस में संग्रहीत।
- यह जानकारी चोर को बैंक खाते खोलने, क्रेडिट कार्ड और अन्य ऋण प्राप्त करने, ये काम करने और यहां तक कि पीड़ित की पहचान का उपयोग करके अपराध करने में सक्षम बनाती है।
- धोखाधड़ी से परे, अपराधी चेहरे की पहचान तकनीक से पीड़ितों का पीछा कर सकते हैं या उन्हें परेशान कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, सार्वजनिक स्थान पर लिए गए स्नैपशॉट का उपयोग स्टॉकर्स द्वारा रिवर्स इमेज सर्च करने के लिए किया जा सकता है ताकि वे अपने लक्ष्यों के बारे में अधिक जान सकें, जिसमें वे कौन हैं और कहां रहते हैं।

- इसके अतिरिक्त, व्यवहार को अपराधी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले पीड़ितों को चोट लग सकती है क्योंकि प्रौद्योगिकी अपराध कानून की तुलना में तेजी से आगे बढ़ता है।

अगले कदम:

- पुट्टस्वामी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है, यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी। इसके अलावा, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाना चाहिए, तो सरकार को यह दिखाना होगा कि कार्रवाई अधिकृत है, आवश्यक है, हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुपात में है, और एक उचित उद्देश्य को आगे बढ़ाती है।

GURU DEEKSHAA IAS

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA